

## उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, 1972)

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 4 जनवरी, 1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 10 जनवरी, 1972 की बैठक में स्वीकृत किया।]

['भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 19 जनवरी, 1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 22 जनवरी, 1972 ई० को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 में निम्नलिखित प्रयोजनों के हेतु आगे संशोधन करने के लिए,

उत्तर प्रदेश अधि-  
नियम संख्या 45,  
1958

### अधिनियम

भारत गणराज्य के बाइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

- 1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम
- 2—उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) में शब्द "उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय" के स्थान पर शब्द "गोविन्द वल्लभ पंत कृषि एवं प्रायोगिक विश्वविद्यालय" रख दिये जायें। उत्तर प्रदेश अधि-  
नियम संख्या 45,  
1958 की धारा  
3 का संशोधन
- 3—मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—  
" (ट) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का एक प्रतिनिधि, और" । धारा 10 का  
संशोधन
- 4—मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (3) में प्रयुक्त शब्दों 'दो पदावधियों' के स्थान पर शब्द 'तीन पदावधियों' रख दिये जायें। धारा 11 का  
संशोधन
- 5—मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्—  
" (2) कृषि प्रयोग केन्द्र का एक संचालक होगा जो उपकुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा और उनके प्रति उत्तरदायी होगा ।" धारा 18 का  
संशोधन
- 6—मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्—  
" (2) एक प्रसार संचालक होगा जो उपकुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा और उनके प्रति उत्तरदायी होगा ।" धारा 19 का  
संशोधन
- 7—उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1971, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश  
अध्यादेश संख्या  
17, 1971 का  
निरस्तन

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 6 जनवरी, 1972 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।]

**UTTAR PRADESH KRISHI VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN)  
ADHINIYAM, 1972**

(U. P. ACT No. 5 OF 1972)

*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Krishi Vishwavidyalaya  
(Sanshodhan) Adhiniyam, 1972]*

AN

ACT

to further to amend the Uttar Pradesh Agricultural University Act, 1958.

It is HEREBY enacted in the Twenty-Second Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Krishi Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1972. Short title.
2. In section 3 of the Uttar Pradesh Agricultural University Act, 1958 (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (1), for the words "Uttar Pradesh Krishi Vishwavidyalaya" the words "Govind Ballabh Pant Krishi Evam Prodyogik Vishwavidyalaya" shall be substituted. Amendment of section 3 of U. P. Act 45 of 1958.
3. In section 10 of the principal Act in sub-section (1), for clause (j) the following clause shall be substituted, namely—  
    “(j) One representative of the Indian Council of Agricultural Research.  
    and” Amendment of section 10.
4. In section 11 of the principal Act, in sub-section (3), for the words "two terms" the words "three terms" shall be substituted. Amendment of section 11.
5. In section 18 of the principal Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely—  
    “(2) There shall be a Director of the Experiment Station who shall be appointed by and be responsible to the Vice-Chancellor” Amendment of section 18.
6. In section 19 of the principal Act, for sub-section (2) the following sub-section shall be substituted, namely—  
    “(2) There shall be a Director of Extension who shall be appointed by and be responsible to the Vice-Chancellor” Amendment of section 19.
7. The Uttar Pradesh Krishi Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhyadesh, 1971, is hereby repealed. Repeal of U. P. Ordinance no. 17, 1971.

---

\*(For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated January 6, 1972.)

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Council on January 4, 1972 and by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on January 10, 1972.)

(Received the Assent of the Governor on January 19, 1972 under Article 200 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated January 22, 1972.)